भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1383
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः आम उत्पादकों की सहायता के लिए राहत उपाय
1383. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में विशेषकर आम उत्पादकों की सहायता के लिए फल प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, जो आम की कीमतों में अचानक और भारी गिरावट के कारण साल-दर-साल नुकसान उठा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को पता है कि आम उत्पादक किसान मूल खेती लागत और परिवहन लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) क्या विशेषकर रामनगर जिले में, जहाँ फसल का नुकसान कथित तौर पर 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक पहुँच गया है और अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, आम की फसल के नुकसान के लिए कोई विशेष राहत उपाय या मुआवजा प्रस्तावित किया गया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार स्वयं फल प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित नहीं करती है। तथापि, सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिनके अंतर्गत कर्नाटक राज्य सहित देश भर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के अंतर्गत, बेंगलुरु दक्षिण जिले के चन्नपटना तालुक और हावेरी जिले के हनागल तालुक में बहु-बागवानी उपज प्रबंधन, भंडारण, प्रसंस्करण और संरक्षण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

(ख) से (घ): किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, सरकारें कृषि और बागवानी वस्तुएं ,जो जल्दी खराब होने वाली प्रकृति की है और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कवर नहीं हैं, की खरीद के लिए पीएम-आशा के तहत एक घटक, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को कार्यान्वित करती हैं, इस हस्तक्षेप का उद्देश्य चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाती है तब इन वस्तुओं के उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना है। शर्त यह है कि पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाली हानि का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार है।

सरकार ने वर्ष 2024-25 सीज़न से बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत भावांतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक प्रारंभ किया है ताकि जल्दी खराब होने वाली फसलों के किसानों को बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे फसल की वास्तविक खरीद करें या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करें।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 सीजन से, सरकार ने किसानों के हित में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एक और घटक को शामिल किया है जिसके तहत उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक परिवहन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को शीर्ष फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

*****